विचार बिन्दु

संसार के दुःखियों में पहला दुःखी निर्धन है। उससे दुःखी वह है जिसे किसी का ऋण चुकाना हो। इन दोनों से अधिक दुःखी वह है, जो सदा रोगी रहता हो और सबसे दुःखी वह है, जिसकी पत्नी दुष्टा हो। –विदुरनीति

वागड़ में मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट: ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत और आदिवासी किसानों की समृद्धि की कुंजी

भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ हैं–ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि। संयोग से इन दोनों राष्ट्रीय उद्देश्यों का समाधान दक्षिण राजस्थान के वागड़–मेवाड़ क्षेत्र की मक्का फसल में छिपा हुआ है। आज जब केंद्र सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E-20) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, तब राजस्थान का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक क्षेत्र इस औद्योगिक क्रांति से अब भी अछूता है। यह केवल एक औद्योगिक अवसर का नुकसान नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी किसानों के भविष्य के साथ अन्याय भी है।

राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20 लाख मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है। इसमें से लगभग 70 से 80 प्रतिशत उत्पादन अकेले मेवाड़–वागड़ क्षेत्र–बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा–से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, राज्य के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 10 से 15 लाख मीट्रिक टन हिस्सा इसी क्षेत्र की देन है। इसलिए यदि किसी स्थान को राजस्थान का 'मक्का हब' या "Maize Bowl" कहा जा सकता है, तो वह निःस्संदेह वागड़–मेवाड़ क्षेत्र ही है। विडम्बना यह है कि जहाँ राज्य का अधिकांश मक्का पैदा होता है, वहीं आज तक एक भी बड़ा मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित नहीं किया गया है।

इसका सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के आदिवासी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, किन्तु स्थानीय किसानों को भंडारण, प्रसंस्करण उद्योगों और संगठित खरीद व्यवस्था के अभाव में बिचौलियों के हाथों अपनी उपज मात्र 1,400 से 1,600 प्रति क्विंटल पर बेचनी पड़ती है। अर्थात् प्रत्येक क्विंटल पर किसान को 800 से 1,000 तक का सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि अधिक उत्पादन करने के बावजूद किसान समृद्ध नहीं हो पा रहा है। यदि वागड़ में एथेनॉल संयंत्र स्थापित हो जाए और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से सीधी खरीद की व्यवस्था हो, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होगा। इससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ाने का राष्ट्रीय उद्देश्य भी साकार होगा।

वागड़ क्षेत्र में एथेनॉल प्लांट लगाने का सबसे बड़ा आधार केवल मक्का उत्पादन नहीं, बल्कि यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अनूठा संयोजन है। माही बजाज सागर परियोजना के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग हेतु अपेक्षाकृत बेहतर जल उपलब्ध है। आधुनिक Zero Liquid Discharge तकनीक अपनाकर जल का अधिकांश भाग पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों तथा गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों से निकटता उद्योग के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है।

आज आवश्यकता केवल दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। वागड़ में मक्का पहले से है, पानी है, किसान हैं, सड़कें हैं और सरकारी नीतियाँ भी उपलब्ध हैं। यदि इन सबको एक साझा विकास मॉडल में जोड़ा जाए तो आने वाले वर्षों में दक्षिण राजस्थान देश के प्रमुख जैव ईंधन केंद्र के रूप में उभर सकता है। समय आ गया है कि राजस्थान सरकार वागड़ क्षेत्र को केवल कृषि उत्पादन का क्षेत्र न माने, बल्कि उसे भारत की हरित ऊर्जा क्रांति का प्रवेश द्वार बनाने का साहसिक निर्णय ले। ऐसा निर्णय न केवल हजारों आदिवासी परिवारों की तकदीर बदलेगा, बल्कि "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को भी नई शक्ति प्रदान करेगा।

यदि बांसवाड़ा अथवा चित्तौड़गढ़ में 200 KLPD क्षमता का आधुनिक मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाए, तो प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख टन मक्का की आवश्यकता होगी। इससे हजारों किसानों की उपज का सुनिश्चित क्रय संभव होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। परिवहन, गोदाम, पैकेजिंग, मशीन रखरखाव, प्रयोगशालाएँ, कृषि सेवाएँ और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। वागड़ से गुजरात की ओर होने वाला मौसमी पलायन भी काफी हद तक रुक सकेगा।

इस उद्योग का लाभ केवल एथेनॉल तक सीमित नहीं है। मक्का से एथेनॉल बनने के बाद जो DDGS (Distillers Dried Grains with Soluble) प्राप्त होता है, वह उच्च प्रोटीनयुक्त पशु आहार है। इससे डेयरी और पोल्ट्री उद्योग को भी नया आधार मिलेगा। अर्थात् एक ही उद्योग से कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्यम–तीनों क्षेत्रों को समान रूप से लाभ होगा।

हालाँकि किसी भी औद्योगिक परियोजना की सफलता केवल निवेश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्थानीय समाज के विश्वास पर भी आधारित होती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में 500 करोड़ का प्लांट रुक गया। कारण था "विकास बनाम पर्यावरण" का टकराव। टिब्बी क्षेत्र कृषि के लिए पूरी तरह भूजल पर निर्भर था और किसानों का तर्क था कि यह प्रोजेक्ट भारी मात्रा में पानी खींचेगा जिससे जलस्तर गिर जाएगा। उनकी यह आशंका पूरी तरह तर्कसंगत थी इसके विपरीत वागड़ क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर जल उपलब्धता होने के कारण ऐसी आशंकाएँ काफी कम हैं। फिर भी परियोजना स्थापित करते समय ग्राम सभाओं की सहमति, पर्यावरणीय पारदर्शिता, जल संरक्षण तथा स्थानीय किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही सहभागी विकास का सही मॉडल होगा।

सौभाग्य से केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने जैव ईंधन उद्योग के लिए अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं। ब्याज अनुदान, औद्योगिक भूमि पर रियायत, बिजली शुल्क में छूट तथा FPO को वित्तीय सहायता जैसी योजनाएँ पहले से मौजूद हैं। आवश्यकता केवल इन नीतियों को वागड़ क्षेत्र तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने की है।

राजस्थान सरकार यदि इस दिशा में गंभीर पहल करे तो पहले चरण में बांसवाड़ा अथवा चित्तौड़गढ़ में एथेनॉल निवेश सम्मेलन आयोजित कर देश की प्रमुख जैव ईंधन कंपनियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद RIICO द्वारा उपयुक्त औद्योगिक भूमि, जल, बिजली और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास कर परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही कृषि विभाग को किसानों और FPO को अनुबंध खेती तथा गुणवत्ता आधारित उत्पादन का प्रशिक्षण देना चाहिए।

वागड़ क्षेत्र लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत पीछे रहा है। यहाँ के आदिवासी किसान कठिन परिस्थितियों में खेती करते हैं, फिर भी उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल उन्हें नहीं मिल पाता। यदि मक्का आधारित एथेनॉल उद्योग स्थापित होता है तो यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं होगी, बल्कि आदिवासी अंचल की आर्थिक संरचना को बदलने वाला ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। इससे कृषि लाभकारी बनेगी, युवाओं को स्थानीय रोजगार मिलेगा, राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।

आज आवश्यकता केवल दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छाशक्ति की है। वागड़ में मक्का पहले से है, पानी है, किसान हैं, सड़कें हैं और सरकारी नीतियाँ भी उपलब्ध हैं। यदि इन सबको एक साझा विकास मॉडल में जोड़ा जाए तो आने वाले वर्षों में दक्षिण राजस्थान देश के प्रमुख जैव ईंधन केंद्र के रूप में उभर सकता है।

समय आ गया है कि राजस्थान सरकार वागड़ क्षेत्र को केवल कृषि उत्पादन का क्षेत्र न माने, बल्कि उसे भारत की हरित ऊर्जा क्रांति का प्रवेश द्वार बनाने का साहसिक निर्णय ले। ऐसा निर्णय न केवल हजारों आदिवासी परिवारों की तकदीर बदलेगा, बल्कि "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को भी नई शक्ति प्रदान करेगा।

–अतिथि सम्पादक,
प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया,
विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञानं) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

जनजातीय विकास का नया अध्याय: संवेदनशील नेतृत्व से समावेशी राजस्थान की ओर

बाबूलाल खराड़ी

लोकतांत्रिक सरकार की सफलता का वास्तविक आकलन इस बात से होता है कि विकास की धारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँचती है। राज्य के सबसे वंचित, दूरस्थ और सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को सुशासन का सबसे सशक्त प्रमाण माना जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को विशेष प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की हालिया उपलब्धियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, कृषि, संस्कृति, खेल, आजीविका और आधारभूत सुविधाओं को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक सहभागी बनाना है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। इसी दृष्टि से जनजातीय छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में मिलने वाले मेस भत्ते में लगातार वृद्धि की गई है। वर्ष 2024–25 में 2,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा वर्ष 2025–26 में इसे बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं खेल अकादमियों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मेस भत्ता 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यह निर्णय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक आधारभूत ढांचे का भी तेजी से विस्तार किया गया है। अनेक नए आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय तथा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की क्षमता बढ़ाई है। वर्तमान में विभाग द्वारा 451 आश्रम छात्रावास, 57 आवासीय विद्यालय तथा अनेक ईएमआरएस संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 46 हजार विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए जनजातीय बालिकाओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना भविष्य की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला कदम है।

महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय पहलें की गई हैं। मां–बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत शिक्षाकर्मियों, महिला सहयोगिनियों तथा स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में लगातार दो वर्षों तक 10–10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में 3,276 मां–बाड़ी एवं डे–केयर केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 86 हजार से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। पोषण सुधार के लिए श्रीअन्न आधारित भोजन तथा स्थानीय भाषाओं में प्राइमर विकसित करने जैसी पहलें जनजातीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण का उदाहरण हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी सरकार ने जनजातीय अंचलों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। क्षेत्र में 4,538 स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिकल सेल रोग के निदान एवं जागरूकता के लिए उदयपुर में सेंटर ऑफ कम्पीटेंस स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला जनजातीय समुदाय को समर्पित टेलीमेडिसिन केन्द्र भी जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नई उम्मीद लेकर आया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में 18 मल्टी–पर्पज केन्द्रों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है, जिनमें अधिकांश का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं का नया आधार विकसित होगा।

सरकार ने सामाजिक विकास और आर्थिक सशक्तीकरण पर समान रूप से ध्यान दिया है। नौ जिलों में 556 वनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से लगभग 161 लाख महिला सदस्यों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें आंवला, शहद, महुआ और इमली जैसे वनोपजों का प्रसंस्करण एवं विपणन होगा। इसके अतिरिक्त छह ट्राइबल मल्टी–पर्पज मार्केटिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे जनजातीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि क्षेत्र में भी जनजातीय किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। लाखों किसानों को निःशुल्क संकर मक्का तथा हाइब्रिड सब्जी बीज उपलब्ध कराए गए हैं। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। कृषि को आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने की यह नीति दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ने वाली सिद्ध हो सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को भी विकास के एजेंडे का हिस्सा बनाया है। साँझ माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के माध्यम से जनजातीय लोककला, चित्रकला, वाद्ययंत्र, नृत्य, गायन तथा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालयों के साथ समझौते किए गए हैं, जिससे परंपरागत ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठों के गठन की स्वीकृति भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल है। इससे लंबे समय से लंबित वनाधिकार संबंधी मामलों के शीघ्र समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

जनजातीय गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर व्यापक जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किया गया। पूरे प्रदेश में हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय समाज की ऐतिहासिक भूमिका और सांस्कृतिक योगदान को सम्मान दिया गया। इसी प्रकार जन भागीदारी अभियान–सबसे दूर, सबसे पहले के अंतर्गत हजारों गाँवों में आयोजित सैचुरेशन शिविरों से लगभग 23 लाख लोग लाभान्वित हुए। यह प्रशासन को जनजातीय समाज के द्वार तक ले जाने का सशक्त प्रयास है।

खेलों में भी जनजातीय प्रतिभाएं राजस्थान का गौरव बढ़ा रही हैं। एशियन लैक्रोस प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन तक, राज्य की जनजातीय बालक–बालिकाएं यह सिद्ध कर रहे हैं कि अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती। सरकार द्वारा खेल आधारभूत ढांचे और प्रशिक्षण पर दिया जा रहा विशेष बल इसी दिशा में महत्वपूर्ण निवेश है। विकास का मूल्यांकन घोषणाओं के धरातल पर दिखाई देने वाले प्रभाव से होता है। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे व्यापक कार्यों से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही है।

–बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री।

SEBI की क्लोजिंग ऑक्शन व्यवस्था: एक ऐसा सुधार जिसे अधिक ट्रांसपेरेंसी और मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

3 अगस्त 2026 से भारतीय शेयर मार्केट में एक बड़ा बदलाव लागू हुआ। SEBI ves NSE और BSE के एफ एंड ओ शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (Closing Auction Session - CAS) शुरू किया। इस सुधार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था – शेयरों की क्लोजिंग प्राइस को अधिक निष्पक्ष तरीके से तय करना, दिन के अंत में संभावित प्राइस मैनिपुलेशन को रोकना और भारतीय पूंजी बाजार को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।

इस सुधार की मंशा निश्चित रूप से सराहनीय है। बेहतर प्राइस डिस्कवरी और मजबूत मार्केट इंटीग्रिटी हर निवेशक के हित में है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के पहले ही दो कारोबारी दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार बंद होने के अंतिम मिनटों में कुछ शेयरों में असामान्य उतार–चढ़ाव देखने को मिला। इससे यह संकेत मिला कि सुधार का उद्देश्य भले सही हो, लेकिन इसकी वर्तमान व्यवस्था को और अधिक सावधानी से परखने की आवश्यकता है।

हर बड़ा मार्केट सुधार शुरुआती दौर में चुनौतियों से गुजरता है। लेकिन जब किसी व्यवस्था का सीधा असर ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस पर पड़ता हो – जो सेटलमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स सेटलमेंट का सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है – तब यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया पर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा बना रहे। खुदरा निवेशकों और ट्रेडर्स की चिंताओं को बदलाव का विरोध मानने के बजाय, नियामकों को इन्हें सकारात्मक सुझाव के रूप में देखना चाहिए। आखिरकार, किसी भी पूंजी बाजार की सबसे बड़ी ताकत निवेशकों का विश्वास ही होता है।

नई व्यवस्था से सामने आए प्रमुख जोखिम

1. क्लोजिंग प्राइस में अचानक बदलाव

कंटीन्यूअस ट्रेडिंग की लास्ट ट्रेडेड प्राइस और ऑक्शन के बाद तय हुई ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस में बड़ा अंतर आ सकता है। इसका सीधा असर पड़ता है - मार्क–टू–मार्केट प्रॉफिट–लॉस, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स सेटलमेंट, ओवरनाइट पोजीशन, अगले दिन की ट्रेडिंग रणनीति

यदि क्लोजिंग प्राइस लगातार ट्रेड हो रही मार्केट प्राइस से काफी अलग हो, तो उसकी प्रतिनिधिकता (ेंजिर्हूंगनहो) पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

2. ओवरनाइट रिस्क बढ़ना

लाखों ट्रेडर्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन रातभर होल्ड करते हैं। यदि ऑक्शन के कारण क्लोजिंग प्राइस बदल जाती है, तो अगले दिन नए रेफरेंस प्राइस के साथ ट्रेडिंग शुरू होती है। इससे अतिरिक्त मार्जिन, अधिक अनिश्चितता और ओवरनाइट रिस्क बढ़ सकता है।

3. शुरुआती चरण में कम लिक्विडिटी –क्लोजिंग ऑक्शन तभी प्रभावी होती है जब पर्याप्त लिक्विडिटी और व्यापक भागीदारी हो। यदि शुरुआती चरण में भागीदारी सीमित रहती है, तो मामूली बाय–सेल इम्बैलेंस भी कीमतों में असामान्य बदलाव ला सकता है। इससे प्राइस डिस्कवरी की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

4. इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज– बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास – एडवांस्ड ट्रेडिंग एल्गोरिदम, क्वांटिटेटिव मॉडल, डेडिकेटेड डीलिंग डेस्क, उच्च पूंजी, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध होते हैं। इसके विपरीत अधिकांश रिटेल इन्वेस्टर्स के पास न रियल–टाइम ऑक्शन एनालिटिक्स होती है और न ही ऑक्शन ऑर्डर डायनेमिक्स की पर्याप्त जानकारी। यह टेक्नोलॉजी और सूचना की असमानता पैदा करती है।

5. – क्लोजिंग प्राइस में अंतर

यदि दोनों एक्सचेंजों पर क्लोजिंग ऑक्शन के परिणाम अलग–अलग आते हैं, तो इससे – आर्बिट्राज के अवसर, ऊंइ और इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर, वैल्यूएशन में अंतर, हेजिंग की जटिलताएँ, निवेशकों में भ्रम, पैसिव फंड्स की अतिरिक्त लागत जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

6. फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर प्रभाव

क्लोजिंग प्राइस का उपयोग – ऑप्शन सेटलमेंट, फ्यूचर्स मार्क–टू–मार्केट, पोर्टफोलियो मार्जिनिंग, इंस्टीट्यूशनल एनएवी, रिस्क मॉडल, पैसिव फंड रीबैलेंसिंग में होता है। इसलिए ऑक्शन आधारित प्राइस मूवमेंट का प्रभाव पूरे डेरिवेटिव्स मार्केट तक पहुँच सकता है, विशेषकर वीकली और मंथली एक्सपायरी के दिनों में।

7. ट्रांसपेरेंसी की कमी

अधिकांश रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी नहीं जानते – ऑक्शन प्राइस कैसे तय होती है?, बाय–सेल इम्बैलेंस का कितना प्रभाव पड़ता है?, ऑक्शन में कौन भाग लेता है?, क्या पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध है? जब जानकारी सीमित होती है, तब अटकलें बढ़ती हैं और भरोसा घटता है।

8. रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास

मार्केट वोलैटिलिटी स्वीकार की जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया पर अनिश्चितता नहीं। यदि निवेशकों को लगे कि दिन की सबसे महत्वपूर्ण प्राइस ऐसी व्यवस्था से तय हो रही है जिसे वे न समझते हैं और न उसमें प्रभावी भागीदारी कर सकते हैं, तो धीरे–धीरे उनका विश्वास कमजोर पड़ सकता है।

अब जरूरत है अधिक ट्रांसपेरेंसी की

इस अचानक किये गए बदलाव में एक अजीब सी मैनीपुलेशन या स्कैम की गंध आ रही है अतः नई व्यवस्था के शुरुआती कुछ महीनों को ऑब्जर्वेशन पीरियड माना जाना चाहिए।

SEBI, NSE और BSE को प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस के बाद निम्नलिखित आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए – कुल ऑक्शन टर्नओवर, भाग लेने वाले ट्रेडिंग मेंबर्स की संख्या, उनके द्वारा किये गए सौदों की पूरी जानकारी जिसमें कंपनी का नाम और शेयर्स की संख्या की स्पष्ट जानकारी, बाय–सेल इम्बैलेंस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का अंतर, र्ऍ्ऍ क्लोजिंग प्राइस तुलना, असामान्य ऑक्शन एडजस्टमेंट वाले शेयर, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में ऑक्शन की हिस्सेदारी, ऐसे मामले जहाँ ऑक्शन प्राइस कंटीन्यूअस मार्केट प्राइस से काफी अलग रही। अधिक ट्रांसपेरेंसी से वास्तविक प्राइस डिस्कवरी और लिक्विडिटी आधारित अस्थायी बदलावों के बीच अंतर स्पष्ट होगा।

आवश्यक सुरक्षा उपाय

स्वतंत्र समीक्षा समिति

SEBI को एक्सचेंजों, ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर संगठनों, शिक्षाविदों और मार्केट विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति जिसमें ऐसे लोग जो 3– 4 दशकों का अनुभव रखते हैं तथा पूर्णतः निष्पक्ष यानि पिछले लगभग एक दशक से शेयर बाजार से सम्बंधित किसी भी संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ना हो, गठित करनी चाहिए, जो पहले छह महीनों की समीक्षा कर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे।

छह महीने बाद औपचारिक समीक्षा

SEBI को पहले से घोषित करना चाहिए कि छह महीने बाद निम्न आधारों पर व्यवस्था की समीक्षा होगी – ऑक्शन लिक्विडिटी, प्राइस एफिशिएंसी, वोलैटिलिटी, सर्विलांस निष्कर्ष, इन्वेस्टर फीडबैक

न्यूनतम लिक्विडिटी मानक

यदि किसी शेयर में ऑक्शन भागीदारी पूर्व निर्धारित सीमा से कम हो, तो हाइब्रिड प्राइस डिस्कवरी या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

स्मॉल इन्वेस्टर्स / रिटेल भागीदारी बढ़ाना

एक्सचेंजों को – जागरूकता अभियान, सरल ऑर्डर प्लेसमेंट, रियल–टाइम एजुकेशनल सामग्री के माध्यम से रिटेल भागीदारी बढ़ानी चाहिए। इन्वेस्टर एजुकेशन

निवेशकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए – क्लोजिंग ऑक्शन कैसे काम करती है। ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस कैसे तय होती है। ओवरनाइट पोजीशन के जोखिम क्या हैं। ऑक्शन ऑर्डर कैसे लगाए जाते हैं। कंटीन्यूअस ट्रेडिंग और ऑक्शन ट्रेडिंग में क्या अंतर है।

मजबूत सर्विलांस

SEBI को विशेष निगरानी रखनी चाहिए – असामान्य ऑक्शन ऑर्डर्स, प्रतिभागियों का अत्यधिक संकेंद्रण, बार–बार होने वाला प्राइस डिस्टॉर्शन, क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने वाली क्रॉस–मार्केट गतिविधियाँ, कंटीन्यूअस मार्केट और ऑक्शन प्राइस के बीच लगातार बड़ा अंतर

समय–समय पर अनाम (Anonymised) सर्विलांस रिपोर्ट सार्वजनिक करना भी उपयोगी होगा।

नियमित सार्वजनिक रिपोर्ट

प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए – ऑक्शन एफिशिएंसी, लिक्विडिटी ग्रोथ, प्राइस क्वालिटी, रिटेल पार्टिसिपेशन, – कन्वर्जेंस, सर्विलांस निष्कर्ष, अंतरराष्ट्रीय तुलना, आवश्यक नियामकीय सुधार

सुधार तथ्यों के आधार पर होना चाहिए

किसी भी मार्केट सुधार का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों से होना चाहिए। यदि समय के साथ यह व्यवस्था बेहतर प्राइस डिस्कवरी, मजबूत मार्केट इंटीग्रिटी और निवेशक सुरक्षा साबित करती है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि लगातार वोलैटिलिटी, प्राइस डिस्टॉर्शन, घटता रिटेल विश्वास या अन्य अनपेक्षित प्रभाव सामने आते हैं, तो को आवश्यक संशोधन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मजबूत नियामक वही होता है जो अनुभव और तथ्यों के आधार पर अपनी नीतियों को लगातार बेहतर बनाता रहे।

निष्कर्ष–––भारतीय पूंजी बाजार ने तकनीक, ट्रांसपेरेंसी और मजबूत रेगुलेशन के कारण वैश्विक पहचान बनाई है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन भी भविष्य में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है। लेकिन इसकी सफलता केवल लागू होने से नहीं, बल्कि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के विश्वास से तय होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स आधुनिकीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि भारत की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस तकनीकी रूप से सही होने के साथ–साथ निष्पक्ष, पारदर्शी, वास्तविक मार्केट कंसेंसस पर आधारित और सभी निवेशकों के लिए भरोसेमंद भी हो।

SEBI के पास यह विश्वास और मजबूत करने का अवसर है। अधिक ट्रांसपेरेंसी, विस्तृत डेटा, सभी हितधारकों से संवाद और स्वतंत्र पोस्ट–इम्प्लीमेंटेशन समीक्षा इस सुधार को अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ बना सकती है। किसी भी मार्केट सुधार की असली सफलता उसके लागू होने में नहीं, बल्कि हर निवेशक का स्थायी विश्वास जीतने में होती है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 6 अगस्त, 2026

सावन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, भरणी नक्षत्र रात्रि 8:19 तक, गंड योग दिन 3:01 तक, बालव करण प्रातः 7:48 तक, चन्द्रमा रात्रि 1:53 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कर्क, चन्द्रमा–मेष, मंगल–मिथुन, बुध–कर्क, गुरू–कर्क, शुक्र–कन्या, शनि–मीन राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज यमघट योग रात्रि 8:19 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:36 तक, चर 10:51 से 12:33 तक, लाभ–अमृत 12:33 से 3:50 तक, शुभ 5:29 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।

वृष
आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

मिथुन
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिलेगा।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। आज विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
घर–परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये–पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य योजना बनेगी। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार होगा।